(सेवा केन्द्र) में आबंटितियों की शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जाता है;

(ख) क्या यहां पर अधिकांशतः सड़कें टूटी हुई हैं और बिजली के मीटर बक्सों पर दरवाजे नहीं हैं;

(ग) यहां पर कितने मकान ऐसे हैं जिनमें कई वर्षों से फ्लश टंकियां खराब पड़ी हैं और इन्हें शिकायत करने पर भी ठीक नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं, रोजमर्रा की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। एजेंन्सी से संबंधित शिकायतों पर उचित प्रक्रिया के पश्चात् कार्रवाई की जाती है।

(ख) सामान्यतः सड़कें अच्छी स्थिति में हैं और बिजली के मीटर बक्स दरवाजे सहित दिये गये हैं। इन से संबंधित कोई शिकायतें सेवा केन्द्र में प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ग) और (घ) इस समय 1392 मकानों में फ्लश टंकियां खराब पड़ी हैं। उनकी मरम्मत करने/बदलने की कार्यवाई की जा रही है।

बिहार के आरा शहर में सड़कों की दशा

3098. **मौलाना ओबेदुल्ला खान आज़मी:** क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार में भोजपुर जिले के मुख्यालय-आरा शहर में सड़कों की दशा काफी दयनीय है;

(ख) क्या सरकार आरा शहर के सड़कों की मरम्मत और विकास के लिए कोई कार्रवाई करेगी; और

(ग) यदि हां, तो कब तक?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) सरकार ने 81.56 लाख रु० की अनुमोदित लागत पर बिहार के भोजपुर जिले के आरा कस्बे को छठी योजना से आई०डी०एस०एम०टी० स्कीम के अन्तर्गत पहले ही शामिल कर दिया है जिसमें यातायात और परिवहन घटक शामिल है। तदनुसार, छठी और सातवीं योजनाओं में कस्बों को 39.00 लाख रु० की केन्द्रीय सहायता जारी की गई। छठी योजना के सभी कस्बों के लिए 31.3.1991 से केन्द्रीय सहायता बन्द कर दी गई थी। सड़कों का रख-रखाव राज्य सरकारें द्वारा किया जाता है।

बहुउद्देश्य कानपुर बराज़

3099. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बहुउद्देश्य कानपुर बराज़ निर्माण के लिए केन्द्र के अंश के रूप में मात्र 6 करोड़ रुपये ही उपलब्ध कराये हैं जबकि इसी अवधि में राज्य सरकार ने उक्त उद्देश्य के लिए 47.57 करोड़ रुपये जारी किये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इस बराज़ की लागत का आधा भाग केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाना है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में शेष 17.12 करोड़ रुपये की राशि को कब तक जारी किया जाएगा और केन्द्र द्वारा नियमित अंशदान के लिए क्या व्यवस्था की गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) केन्द्र सरकार ने अब तक राज्य सरकार को 6 करोड़ रु० प्रदान किए हैं। राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त योजना के लिए राज्य सरकार ने 54.12 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं।

(ख) आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने गंगा बैराज योजना अनुमोदित की है जिसमें 263.40 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर जल आपूर्ति घटक भी शामिल हैं इस लागत का 50% भाग केन्द्र सरकार द्वारा ऋण सहायता के रूप में मुहैया कराया जाएगा।

(ग) भविष्य में धनराशि संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर प्रदान की जाएगी।

Selection of assistant director in DOP

3100. SHRI ONWARD L. NONGTDU: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a post of Assistant Director (O.L.) on deputation was advertised in the Employment News, dated the 2nd May, 1998 by the Department of Publication, Civil Lines, Delhi, a subordinate office of the Ministry;